बीके अस्पताल में इलाज भले ही न मिले, भ्रष्टाचार और फ़र्जीवाड़े की कमी नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले भर में इलाज के लिये प्राइवेट अस्पताल तथा ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। बीके अस्पताल के अधिकारी तो केवल इन सब पर थानेदारी करने के लिये बैठा रखे हैं। इसके अलावा बीके अस्पताल व ज़िले भर के तमाम चिकित्सा केन्द्रों में जो भ्रष्टाचार व लूट का दौर चलाया जा रहा है वह अलग से। फ़िलहाल ठेकेदारी जिसे 'आउट सोर्स' कहा गया है, के माध्यम से जो खुला खेल भ्रष्टाचार का खेला जा रहा है वह बहुत गजब का है।

ठेकेदारी में स्वीपर, सिक्यूरिटी गार्ड वार्ड ब्वाय, लिफ्ट मैंन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी माली-चपरासी आदि के लिये 230 लोग़ों का स्टाफ़ हैं। इन्हें भविष्य निधि व ईएसआई का 2300 रु. काट कर 13700 रु. मासिक वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है। इनमें से दर्जनों लोग ऐसे हैं जिन्होंने न तो कभी अस्पताल को देखा और न ही अस्पताल ने उन्हें देखा। कुछ ऐसे भी हैं जो यदा-कदा अस्पताल में घूम-फ़िर कर शक्ल तो दिखा जाते हैं परन्तु काम यहां कोई नहीं करते।

हाल-फ़िलहाल 'मज़दूर मोर्चा' ने अपनी तहकीकात में पाया कि प्रदीप बैंसला जो नीमका स्थित पॉलटेक्नीक में पढाई कर रहा है और यहां से बतौर वार्ड ब्वाय का वेतन नवम्बर 2020 से ले रहा है जबकि उसकी हाजिरी अक्तूबर से दिखाई जा रही है। जानकार बताते हैं कि वह अजीत सुपरवाइज़र का भतीजा है। रणजीत सिंह नामक एक व्यक्ति को यहां वार्ड ब्वाय दिखा रखा है जो कानपुर में रहता है और अपना काम धंधा कर रहा है जिसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अक्तूबर 2020 से उसके खाते में वेतन जा रहा है। रणजीत सिंह की पत्नी किरण वह महान हस्ती है जो अस्पताल के अधिकारियों को खुश रखती है तथा इस सारे गोरख धंधे का संचालन करती है। किरण कभी खुद यहां बतौर चपरासी आदि के तौर पर ठेकेदारी में आई थी। जब गुलशन अरोड़ा यहां बतौर सीएमओ आये तो वे उस पर इतने मेहरबान हो गये कि इस मकाम तक पहुंचा गये।

ठाकुर रघुविंदर सिंह जो किरण का भतीजा है, कानपुर में रहता है, बतौर स्वीपर उसकी यहां हाजिरी लग रही है नवम्बर 2020 से, पूरा वेतन खाते में जा रहा है। यहां एक और पेच यह भी है कि अब रघुविंदर की जगह रविंदर का नाम चढा

दिया गया है। ठाकुर साहब स्वीपर का काम कैसे करते होंगे सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि काम तो करना ही नहीं हाजरी लगानी हैऔर पैसा मिलना है। ललित और सूबे सिंह नागर सिक्यूरिटी गार्ड हैं जो कभी ड्यूटी पर नहीं देखे गये और वेतन नियमित रूप से लेते आ रहे हैं। कोमल को कभी स्वीपर तो कभी वार्ड ब्वाय, रूबी पांडे को स्वीपर व वार्ड ब्वाय के खाते में लिखा जाता है और इसी तरह अनीता जिसे वार्ड ब्वाय दिखाया गया है ये कभी ड्यूटी पर नहीं आतीं लेकिन हाजरी पूरी होती हैं।

किरण का घरेलू नौकर व परिजन भी पाते हैं वेतन

जो किरण कभी खुद ही ठेकेदारी में यहां मामूली नौकरी करती थी अब घरेलू काम के लिये उसने शिवम को नौकर रखा है। इसके एवज में किरण ने उसका व उसकी पत्नी का नाम भी 230 कर्मचारियों की लिस्ट में चढा रखा है। किरण की दो बहने-ललिता व रानी तथा जीजा राजीव का नाम इन्ही कर्मचारियों की लिस्ट में हैं जो लगातार पूरा वेतन सरकारी खजाने से पा रहे हैं। इन लोग़ों की एक बात तो है कि ये अस्पताल में भले ही तिनका न तोड़ें परन्तु कभी-कभार प्रकट जरूर होते रहते हैं, यानी उनकी श्रेणी में नहीं आते जो कानपुर रहते हैं या किसी संस्थान के छात्र हैं।

लावारिसों का दोहरा शोषण

सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब इतने लोग काम पर ही नहीं आते तो अस्पताल का काम चलता कैसे है? इसके दो जवाब हैं, एक तो यह कि जो सारा दिन काम करते हैं उनकी गैरहाजिरी लगाई जाती है जिसके चलते उन्हें मासिक 6-7 हज़ार मिल पाते हैं; बोल इसलिये नहीं पाते कि यह नौकरी भी कहीं हाथ से न जाती रहे। दूसरा हल यह है कि जहां चार लोग़ों का काम है वहां दो या तीन से ही काम चलाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप काम पूरा एवं सही नहीं होता, यानी गंदगी पड़ी है तो पड़ी है, वार्ड ब्वाय कम हैं तो मरीज़ खुद भुगत लेंगे।

प्रसूती वार्ड में तैनाती की रिश्वत

प्रसूती वार्ड में 'बधाई' के पैसे व अन्य कई तरह की वसूलियों के चलते हर कर्मचारी इस वार्ड में तैनाती चाहता है। लेकिन तैनाती उसी को मिलती है जो किरण को तीन से पांच हजार की रिश्वत दे। इस वार्ड में लगने वाले कम से कम 10 लोगों के हिसाब से किरण के 30 से 50 हज़ार मासिक तो बनते ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि यह सारा खेल किरण अकेली ही खेलती है, इसमें मैट्रन का भी हिस्सा रहता है। रही बात सम्बन्धित डॉक्टरों की तो उनके लिये मोटे माल की सैटिंग इन्हीं कर्मचारियों आदि के द्वारा की जाती है।

ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं

सरकारी खजाने से तो पैसा बतौर वेतन निकलता है वह केवल किरण द्वारा तैयार लिस्ट व लगाई गयी हाजिरी से नहीं निकलता इस पर मैट्रन से लेकर डिप्टी सीएमओ व सीएमओ तक के हस्ताक्षर होते हैं। इनके हस्ताक्षरों से पहले बाकायदा बिल बनाये जाते हैं जो एकाऊंट ब्रांच से पास होते हैं। तमाम कार्यवाही के बाद बिल सरकारी खजाने में भेजे जाते हैं जहां से प्रत्येक दिखाये गये कर्मचारी का वेतन उसके खाते में जाता है।

कानूनी नज़र से देखा जाय तो किरण से लेकर सीएमओ तक के सभी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए सरकार के साथ विश्वासघात एवं धोखा-धड़ी कर रहे हैं। अगर हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ है तो ये तमाम लोग आईपीसी की अनेकों धाराओं में गिरफ़्तार कर सीधे जेल भेजे जा सकते हैं। स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री अनिल विज जो फ़िजूल की लफ़्फ़ाजी करते एवं ईमानदारी का ढोल बजाते घूमते हैं उन्हें यह सब क्यों दिखाई नहीं देता और अब सार्वजनिक तौर पर दिखा दिये जाने पर वे क्या कार्यवाही करते हैं, इसका इन्तज़ार रहेगा।

कर्मचारी यूनियन का बिकाऊ नेता

सुन कर आश्चर्य होता है कि इतनी अंधेर गर्दी व गरीब मज़दूरों का शोषण होता देखने के बावजूद कर्मचारियों का नेता सोनू बाल्मीकि खामोश क्यों है? वहां काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि सोनू सरकार की पक्की नौकरी पर बतौर स्वीपर तैनात है। नेतागिरी के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। यह कर्मचारियों से तो चंदा वसूलता ही है साथ में शोषण व उक्त धोखा-धड़ी के विरुद्ध खामोश रहने के बदले भी कुछ न कुछ वसूली जरूर करता होगा।

अपने कोविड इन्तजाम करने की बजाय, सरकार की नज़र ईएसआईसी पर ही टिकी है

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते सप्ताह उपायुक्त यशपाल यादव, सीएमओ पूनिया, इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर हसीजा, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की ओर से डीन आदि की एक बैठक हुई। विषय था तीसरी लहर से निपटने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना।

इस बैठक में बीके अस्पताल की दुर्दशा को सुधारने पर कोई चर्चा नहीं की गयी। इसका वर्षों से लम्बित पड़ा बिस्तार कार्य पूरा करने, नये पदों का सृजन करने की तो बात छोड़िये बरसों से रिक्त पड़े पदों को भरने तक का कोई जिक्र नहीं किया। ज़िले के इस प्रमुख अस्पताल के अलावा दर्जनों अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति सुधारने, वहां रिक्त पदों को भरने तक कि कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा अस्पतालों के नाम पर जगह-जगह बनी खड़ी बिल्डिंगों के इस्तेमाल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

दो दिन में मोठुका गांव स्थिल अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल चालू कर देने वाली मुख्यमंत्री की घोषणा को तो बिल्कुल ही पी गये। उस अस्पताल को चलाने का कोई जिक्र तक इस बैठक में नहीं हुआ। आज भी वह अस्पताल वीरान है मात्र 15-20 साधारण मरीज़ ही वहां लेटे पड़े हैं क्योंकि वहां न तो आईसीयू और वेंटिलेटर हैं और न ही किसी गंभीर मरीज़ को सम्भालने के लिये वहां प्रशिक्षित स्टाफ़ व डॉक्टर हैं। बैठक में प्राइवेट अस्पतालों के साथ-साथ ईएसआई के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सुदृढ करने पर पूरा ज़ोर लगाया गया। इनसे कहा गया बताते हैं कि बच्चों वाले वार्ड का बिस्तार करें। जहां तक सवाल है प्राइवेट व्यापारिक अस्पतालों का, वे सरकार की कतई कोई परवाह नहीं करते, वे देखते हैं केवल अपना व्यापार तथा मुनाफ़ा। उसी के हिसाब से वे अपने वार्डों को घटाते बढाते हैं। ले-देकर गरीब, बेसहारा मज़दूरों का ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल इनके शिकंजे में फंसा हुआ है जो पहले से ही काफ़ी सुदृढ़ है, उसे और सुदृढ बनाने के लिये प्रशासनिक दिशानिर्देशों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रशासनिक दादागिरी के पिछे एक मात्र कारण मज़दूर आन्दोलन का कमजोर होना है। यदि हरियाणा सरकार को ईएसआई से ही सेवायें लेनी है तो क्यों नहीं अपनी ईएसआई हेल्थ केयर सेवा को सुचारू एवं सुदृढ करती? विदित है कि सेक्टर आठ स्थित 200 बेड के अस्पताल को हरियाणा सरकार ने विरान बना रखा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जितनी डिस्पेंसरियां होनी चाहियें तथा जितना स्टाफ़ होना चाहिये उसका नाम मात्र ही उपलब्ध नहीं है। ख्याली पुलाव पकाने वाले इन अफ़सरों को यह सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? उन्हें केवल ईएसआई कार्पोरेशन द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज ही क्यों दिखाई देता है?

हालात देख कर समझा जा सकता है जब तक मज़दूर वर्ग संगठित होकर सरकार की इस धींगा-मुश्ती का कड़ा विरोध नहीं करेगा, उनके इस अस्पताल का यूं ही दुरूपयोग होता रहेगा।

देखी-सुनी

खबरीलाल

जज साहिबा और पीड़ित महिला की उम्मीद

शहर के एक पॉश इलाके में एक जज साहिबा को सरकार की ओर से किराये पर फ्लैट लेकर रहने के लिए दिया गया। फ्लैट की मालकिन एक महिला ही हैं। कुछ समय बाद जज साहिबा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। जाहिर है कि फ्लैट छोड़ना पड़ेगा और दूसरे शहर जाना पड़ेगा। मकान मालकिन के पास सरकार का परवाना भी आ गया कि अब आपका फ्लैट खाली किया जा रहा है और अगले महीने से आपको किसी भी तरह का कोई किराया नहीं मिलेगा। महिला को लगा कि सरकारी आदेश आ ही चुका है, जज साहिबा 10-15 दिनों में उसका फ्लैट खाली कर देंगी। वो एक महीने का नुकसान सह लेगी। कोई बात नहीं। उसने एक महीना इंतजार किया। जज साहिबा फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं। महिला ने पूछा तो बताया गया कि जज साहिबा को जब दूसरे शहर में फ्लैट मिलेगा, तब खाली होगा। वैसे भी जज साहिबा को ये फ्लैट पसंद है। लेकिन किराये का क्या होगा, इस पर चुप्पी साध ली गई। मकान मालकिन को चाल समझ में आ गई। अब उसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न जाने किनको-किनको उसका फ्लैट खाली न करने की दास्तान लिख मारी। मजदूर मोर्चा ने महिला से संपर्क किया और दस्तावेज मांगे ताकि खबर छापी जा सके। मकान मालकिन ने कहा कि मैंने मोदी जी को लिखा है। मेरा फ्लैट तो चुटकियों में खाली हो जाएगा। मैं अखबार में नहीं छपवानी चाहती, जब मोदी जी के दफ्तर से ऐसे ही एक्शन हो जाएगा। इस कॉलम को लिखे जाने तक महिला का फ्लैट जज साहिबा के कब्जे में है, महिला के पास मोदी जी के दफ्तर से अभी कोई जवाब नहीं आया है।

बेचारे पार्षदों की 'गरिमा' का क्या होगा

एमसीएफ कमिश्नर डॉ गरिमा मित्तल के पास इतना काम है कि बेचारी टिक कर एक दफ्तर में बैठ ही नहीं पाती हैं। खोरी और लकड़पुर गांव में अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वो और भी व्यस्त हो गई हैं। उन्होंने अपने स्मार्ट सिटी आफिस सेक्टर 20 में बुधवार को ओल्ड जोन और तिगांव विधानसभा इलाके के वॉर्ड के पार्षदों की बैठक बुलाई, ताकि आराम से वहां बैठकर सभी पार्षदों की समस्याएं सुनी जा सकें। हालांकि ये बैठक वो एमसीएफ मुख्यालय में बुला सकती थीं लेकिन वहां भीड़ ज्यादा होने के कारण बैठक स्मार्ट सिटी के दफ्तर में रख दी। 11 पार्षद तो अपने तय वक्त पर पहुंच गए लेकिन कमिश्नर गरिमा मित्तल बैठक में नहीं पहुंचीं। एसी गाड़ियों और एसी घरों में रहने वाले पार्षद स्मार्ट सिटी के दफ्तर में बैठे-बैठे पसीना-पसीना हो गए। कमिश्नर नहीं आईं। इसके बाद पार्षद हाय-तौबा मचाते हुए वहां से निकल लिए। ओल्ड जोन थोड़ा वीआईपी इलाका है। यहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के बेटे और सीनियर डिप्टी मेयर देवेन्द्र चौधरी का भी वॉर्ड आता है। पार्षदों ने इसे अपनी घनघोर बेइज्जती माना है और इसे उच्चस्तर पर उठाने का फैसला किया है। लेकिन इन बेचारे पार्षदों को यह नहीं मालूम था कि जब यहां उनकी बैठक का समय हो रहा था तो ठीक उसी समय गरिमा मित्तल डीसी और डीसीपी के साथ खोरी गांव के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। इस समय खोरी सबसे प्राथमिकता का काम पूरे प्रशासन के लिए हो गया है। उसके आगे अफसरों को कुछ सूझ ही नहीं रहा। गरिमा मित्तल नगर निगम के अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और एफएमडीए की भी सर्वेसर्वा हैं। इसलिए वो बेचारी कहां तक एक-एक पार्षद की मतलबी फरियादें सुनती रहें। लेकिन पार्षद को दुनिया जहान से क्या मतलब, उन्हें तो बस अपना वॉर्ड याद रहता है। वॉर्ड में मलाई है, उनकी नजर में बाकी सब फर्जीवाड़ा है।

इस डीसी को रोकने की हुई मांग

हरियाणा में मुस्लिम बहुल मेवात इलाका हर मायने में सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। जहां के लिए योजनाएं बनती हैं लेकिन वो कागजों तक सीमित रहती हैं। उन्हें जमीन पर उतारने के लिए अधिकारी दिलचस्पी नहीं लेते। हालांकि इसके लिए उनके किसी पूर्वाग्रह को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेवात में पोस्टिंग को अधिकारी सजा मानते हैं। वहां गरीबी इतनी है कि रिश्वतखोर अधिकारियों का पेट नहीं भरता है। ऐसे में कौन मेवात में रुकना चाहेगा। लेकिन पहली बार एक डीसी यहां ऐसा आया जिसका तबादला रोकने की मांग मेवात की जनता ने की। नूंह के डीसी धीरेन्द्र खडगटा का दो दिन पहले तबादला कर दिया गया। मेवात के लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए उनका तबादला रोकने के लिए मुहिम चलाई। उनकी जगह कैप्टन शक्ति सिंह को नूंह का डीसी लगाया गया है। धीरेन्द्र खडगटा को खट्टर सरकार ने अंबाला का निगम कमिश्नर नियुक्त किया है। बेहद मिलनसार, ईमानदार और लो प्रोफाइल जिन्दगी जीने वाले 2012 बैच के आईएएस धीरेन्द्र खडगटा ने मेवात की गरीब जनता में अपनी जबरदस्त छवि बना ली थी। उनके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। धीरेन्द्र ने यह छाप सिर्फ मेवात में ही नहीं छोड़ी, वो सोनीपत और कुरुक्षेत्र में भी डीसी रहे और वहां भी उनका चर्चा रहा। कोरोना के दौरान खट्टर ने मेवात में कुछ बैठकें कीं तो उन्हें समझ में आ गया कि इस अफसर का इस्तेमाल तरीके से किया जाना चाहिए। यही वजह है कि खट्टर ने अब उन्हें अपने कट्टर प्रतिद्वंदी अनिल विज के इलाके अंबाला में तैनात कर दिया है। अनिल विज पर एक तरह का अंकुश रहेगा, वे मनमाने ढंग से अंबाला में काम नहीं करा पाएंगे और ईमानदार छवि की वजह से धीरन्द्र खडगटा पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएंगे।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06